मुद्रा बाजार

भारतीय पूंजी बाजार की नई अवधारणा बाई बैंक :

- बाई बैंक का प्रत्यक्ष अर्थ है कपनिया बाजार से अपने शेयर क्रय करके शेष नए शेयरों पर प्रति लाभ में वृद्धि कर सकती है |
- भारत में 31 अक्टूबर,1998 के पूर्व बाई बैंक का प्रावधान नहीं था | 31 अक्तूबर,1998 को एक अध्यादेश के माध्यम से कपनी अधिनयम में संशोधन करके इसका प्रावधान किया गया |

सूक्ष्म वित्त

- वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि समाज के उपेक्षित व निम्न वर्ग के असंख्य लोगों की सस्ती लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाए |
- साख के संबंध में,वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोग वे है जिन्हें माँग के बावजूद साख नहीं दिया जाता है | (जैसे-बचत,बीमा,भुगतान व विप्रेष्ण आदि |
- सूक्ष्म वित्त से आशय उन सभी वित्तीय सेवाओं से है जिनमे छोटी-छोटी मात्रा उन लोगों को मुहैया करायी जाती है जो साधन विहीन है पर जो आर्थिक क्रियाओं को करने योग्य है इन्हे सूक्ष्म वित्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे विशेष रूप से गरीबों पर केन्द्रित रहती है और उनके द्वारा उत्पन्न उत्पाद सूक्ष्म होते है |
- भारत में सूक्ष्म सहायता दो मॉडलों पर आधरित है |
- स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम : बुनकरों,मछुआरों,कारीगरों और कूड़ा बीनने वालों की बड़ी संख्या इन्ही सहायता समूहों द्वारा अपना जीवन स्तर सुधारने में सफल रही है ये संस्थाएं गरीब निवेशकों को अपनी शर्तों पर सूक्ष्म ऋण उपलब्ध करती है ताकि वे कोई उत्पादन कार्य कर देश की मुख्य धारा में आ सकें | इसका सबसे उदाहरण है - बाग्लादेश ग्रामीण बैंक जिसके प्रर्वतक 2006 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद युनुस है |
- **लघु वित्त संस्थाएं :** देश का पहला सूक्ष्म वित्त संस्थान 'बेसिक्स' है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी |
- बैंक संपर्क 1986 में अस्तित्व में आया,जब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कर्नाटक में एक स्वयं सेवी संगठन 'मर्यादा' को पहला औपचारिक ऋण दिया |
- **सूक्ष्म साख :** यह एक ऐसी व्यवस्थ है जो छोटे-मोटे कामगारों को आय अर्जक रोजगार हेतु साख सुविधा उपलब्ध कराता है |
    - मालेगम समिति
- रिजर्व बैंक ने वाई० एच० मालेगाम की अध्यक्षता में एक अमिति का गठन किया गया | जिसे लघु-वित्त क्षेत्र का अध्ययन करने और इसमें सुधार लेन के उपायों को सिफारिश देने को कहा गया |
- इस समिति ने जनवरी 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | जिसकी मुख्य सिफारिशों में है -
- ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज 24% से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- माईक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की एक अलग श्रेणी NBFC-MFI बनाने की सिफारिश की है |

मुद्रा की कुल पूर्ति को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है -

1.चलन मुद्रा
2.बैंक सेवाएं

- चलन मुद्रा में सभी कागजी नोट एवं धात्विक सिक्कों सरकारी कोषागार एवं व्यापारिक बैंकों के पास नकद जमा को छोडकर सम्मिलित किया जाता है |
- बैंक जमाओं में व्यापारिक बैंकों की माँग जमाएं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास होने वाली जमाएं सम्मिलित होती है इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा M_1की संज्ञा दी गई है |

M_2=M_1+डाकघरों के पास बचत बैंक जमाएं

M_3=M_1+बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमाएं

M_4=M_3+डाकघरों की समग्र जमाएं

मुद्रा की कुल पूर्ति =M_1+M_2+M_3+M_4

जहाँ M_3 विस्तृत मुद्रा तथा M1 संकुचित मुद्रा कहलाती है |

जहाँ M_1=जनता के पास मुद्रा+बैंकों की माँग जमा+रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं

मुद्रा आपूर्ति संबंधी रेड्डी की अनुशंसाएं :-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1997 में डिप्टी गर्वनर वाई०वी० रेड्डी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था | जिसने अपनी संस्तुतियां भारतीय रिजर्व बैंक को 24 जून,1998 में सौपी थी | रेड्डी कार्यदल ने निम्न सिफारिश की थी |
- डाकघर बचत बैंक को समुच्चय M_2से निकालकर नये नकदी निधि तरलता समुच्चय L_1में सम्मिलित किया जाना चाहिए |
- समिति ने चार नये मौद्रिक समुच्चयों की चर्चा की है,जिसमें M_0,M_1,M_2तथा M_3तथा तरलता सूचकों (L_1,L_2,L_3) की चर्चा की है |
- समिति ने M_0का आधार मुद्रा याप्रारक्षित मुद्रा कहा |
- रेड्डी कमेटी की तरलता समग्रों की धारणाको रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया |

  50 या 100,पांच से ऊपर के नोट पर रिजर्व बैंक के गर्वनर द्वारा दिया गया वचन I Promise to pay का मतलब है जो कोई नोट रिजर्व बैंक छापता है उसके साथ ही उसके मूल्य के बराबर उसका जनता के प्रति दायित्व बढ़ जाता है | जिसे हम मौद्रिक दायित्व कहते है अर्थात् सरकार मुद्रा का निर्गमन उसके मौद्रिक दायित्व में वृद्धि लाता है मुद्रा यदि निर्गमित करने वाली सभी संस्थाओं के मौद्रिक दायित्व को जोड़ दे तो मुद्रा की पूर्ति प्राप्त हो जायेगी |
- मुद्रा की पूर्ति (M3) में परिवर्तन के स्रोत-

  निर्यात या पूँजी के अंतर्प्रवाह के कारण डॉलर का अंतर्प्रवाह
  ↓ परिणाम
  विदेशी विनियम बाजार में डॉलर ($) की पूर्ति में वृद्धि
  ↓ जिससे
  रूपये की माँग में वृद्धि
  ↓
  डॉलर के रूप में रूपये के मूल्य में वृद्धि
  ↓ (रूपये के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए)
  RBI द्वारा ($) डॉलर का क्रय
  ↓जिससे
  - RBI की विदेशी विनियम सम्पत्ति में वृद्धि

  ↓ जिसकी जगह से
  - RBI के मौद्रिक दायित्व

  ↓ में बढोत्तरी फलस्वरूप
  - M_3 में वृद्धि

मुद्रा की पूर्ति करने की प्रारंक्षित मुद्रा :

- यदि हम प्रारंक्षित मुद्रा (M_0) में मुद्रा गुणक (M) का गुणा करे दे तो हमें मुद्रा की पूर्ति (MS) या Ms प्राप्त हो जायेगी |
- चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंक्षित मुद्रा अत्यधिक शक्तिमान मुद्रा,आधार मुद्रा,प्राथमिक मुद्रा के रूप में जानी जाती है |
- प्रारंक्षित मुद्रा(M_0) से आशय केवल रिजर्व बैंक इण्डिया के निवल मौद्रिक दायित्व से है |
- अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति प्रारंक्षित मुद्रा की कई गुना होगी | प्रारंक्षित मुद्रा की वृद्धि के कारण मुद्रा की पूर्ति में कितनी गुना वृद्धि होगी | इसे मुद्रा गुणक कहते है | यह प्रारंक्षित मुद्रा(RM) में वृद्धि तथा मुद्रा की पूर्ति (M_3) में वृद्धि के बीच संबंध प्रदर्शित करता है |

मौद्रीकरण की माप:

- मौद्रीकरण की माप के लिए धारणएं मिलती है | जिनमें मौद्रीकरण की गहनता की धारणा में गहनता को हम GDP के अनुपात के रूप में औसत M_3की व्यक्त करते है|
- दूसरी धारणा में धारणा में इसकी माप के लिए हम GDP के अनुपात के रूप में औसत को लेते है |

तरलता समायोजना सुविधा :

- नरसिम्हन समिति (1998) की संस्तुति पर LAF को क्रमिक रूप से पहले अंतरिम रूप में 1999 में तथा अंतिम रूप में 2000 में लागू किया गया | दर रेपी दर के माध्यम से बाजार में दिन प्रतिदिन आधार पर तरलता स्मोयोजित करता है

RBI ब्याज की विभिन्न दरों पर बाजार में तरलता की आपूर्ति करता है |

- 20 मार्च,2007 में एक नयी संशोधित LAF स्कीम लागू की गयी थी |
- नयी स्कीम के तहत LAF की अवधि को 7 दिन से घटाकर 1 दिन कर दिया गया |
- नकदी प्रबन्धन को अधिक प्रभावी बनाबे के लिए 28 नवम्बर,2005 को रिजर्व बैंक ने दूसरी LAF सुविधा शुरू की |

अवमूल्यन:

- किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देश की आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन के कारण होता है | अर्थव्यवस्था में परिवर्तन मुद्रा मूल्य को प्रभावित करता है | मुद्रा मूल्य में परिवर्तन उपभोग,विनियम नियन्त्रण,वितरण,रोजगार,कीमत स्तर आदि को प्रभावित करती है |
- इन परिवर्तनों का एक निश्चित क्रम रहता है इन क्रमिक परिवर्तनों को व्यापर चक्र की सज्ञा दी जाती है |
- अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबुझकर कम कर देने से होता है | इससे मुद्रा के आंतरिक मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि दुसरे देश के लिए वह मुद्रा सस्ती हो जाती है |
- अवमूल्यन में देश की मुद्रा की विदेशी विनियम क्रय करने की शक्ति कम हो जाती है |
- इससे निर्यात को प्रोत्साहन आयात का हतोत्साहित होता है |
- अवमूल्यन का उद्देश्य विदेशी निवेशकर्ताओं को पूँजी निवेश हेतु प्रोत्साहन करना है |
- विदेशी मुद्रा विनियम दर RBI द्वारा तय की जाती है जो 1991 से पहले स्थायी थी परन्तु 1991 के बाद यह बाजार के अनुसार परिवर्तित होती है |
    - **भारत में रुपए का अवमूल्यन :**
- भारतीय मुद्रा रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन 20 दिसम्बर,1949 को 30.5% पौड स्टर्लिग के साक्षेप किया गया | उस समय भारत सहित 20 देशों ने अपनी-अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था |
- दूसरी बार 6 जून,1966 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36.5% किया गया |
- तीसरी बार अवमूल्यन,1 जुलाई;1991 को किया गया (8.9% से 10.15%)
- चौथी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन,3 जुलाई,1991 को किया गया | देश की अत्व्यवस्थएं विनियम दर से प्रभावित होती है क्योंकि मुद्रा का विनियम दर पर सफल घरेलू उत्पाद,अवमूल्यन,मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति आदि घटकों को को व्यापक प्रभाव पड़ता है |

    नोट : भारतीय रूपये की अलग पहचान चिन्ह देवनागरी के 'र' व रोमन अक्षर 'r' से मिलते जुलते प्रतीक 'र' के प्रतीक के रूप में स्वीकार करने का फैसला केन्द्रीय मंत्रीमंडल की 15 जुलाई,2010 की बैठक में किया गया |

- यह चिन्ह मुम्बई iiT के स्नातकोत्तर D.Uday kumar द्वारा डिज़ाइन किया गया है |
- अमरीकी डॉलर($),ब्रिटिश पाउण्ड स्टर्लिग(£) जापानी येन(¥) व यूरोपीय यूरो (€) के बाद भारतीय रुपया विश्व की पाँचवीं ऐसी मुद्रा है जिनका अपना अलग पहचान चिन्ह है |

मुद्रा स्फीति :

- मुद्रा स्फीति को मुद्रा का प्रसार भी कहते है मुद्रा प्रसार स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है | जबकि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा उसकी तुलना में मक रहती है | सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है |
- सामान्यता मुद्रा स्फीति उस स्थिति को कहते है जबकि पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में माँग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि हो रही है |
- कैगन पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1956 में मुद्रास्फीति को लोगों लि मुद्राधारिता के ऊपर स्फीति कर के रूप में देखा |

    स्थायी मुद्रास्फीति - इस अवधारण का प्रतिपादन 1981 में (Eckstion) ने किया -

- भारत में स्फीति का सामान्यता WPI आधार पर तथा (CPI-lw) आधार पर व्यक्त किया जाता है |

- मुद्रा स्फीति के उल्ट स्थिति को मुद्रा संकुचन कहा जाता है | इससे मूल्य वृद्धि दर में गिरावट आती है |
- Galloping Inflation के तहत मुद्रास्फीति में अचानक भारी वृद्धि होती है |
- WPI का आधार वर्ष 1993-94 लिया जाता था जिसे वर्तमान में 2004-05 कर दिया गया है |
- भारत में मुद्रा स्फीति की दर को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है -
- अंकदर अंक
- 52 सप्ताह के औसत के आधार पर |
- किसी भी अर्थव्यवस्था में स्फीति की दर को मापने के लिए सामन्यतय दो तरीके प्रयोग में लाये जाते है |
- मूल्य सूचकांक में विभिन्न वर्षो में % परिवर्तन
- GNP या GDP अवस्फीतक में परिवर्तन
    - मुद्रास्फीति में मूल्य सूचकांक के तीन रूप हो सकते है -
- थोक मूल्य सूचकांक
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य निर्दशांक
- कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य निर्दशांक
- भारत में पहला थोक मुय सूचकांक 10 जनवरी,1942 में उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकर कार्यालय में साप्ताहिक स्तर पर होता है इसका आधार वर्ष 1939-100 लिया गया |
- WPI को उत्पादक मूल्य सूचकांक भी कहते है |
- 1999 में थोक मुय सूचकांक को नई श्रृंखला जारी की गई जिसमे 435 वस्तुएं सम्मिलित की गई थी तथा आधार वर्ष 1993-94 के स्थान पर 2000-01 कर दिया गया है|
- मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है | तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में गिरावट होती है इसका मुख्य कारण मौद्रिक आय एवं उत्पादन मात्रा में असंतुलन उत्पन्न होता है |
    - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :
- भारत में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अवधारणा प्रचलन में लाई जाती है |
- श्रमिकेतर शहरी कर्मचरियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक |
- औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक |
- कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक |
- ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- इसमे CPI-IW सबसे प्रचलित सूचकांक है क्योंकि मजूदरी के सूचीकरण के लिए इसका प्रयोग सरकार तथा संगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है |
- **स्फीति और मुद्रा संकुचन का प्रभाव**

वर्ग	मुद्रास्फीति	मुद्रा संकुचन
उत्पादनक वर्ग	लाभावित होता है	हानि होती है
व्यापारी वर्ग विनियोग कर्ता	लाभावित होता है	हानि होती है
निश्चित आय वाले	हानि होती है	लाभावित होता है
अनिश्चित आय वाले	लाभावित होता है	हानि होती है
ऋणी	लाभावित होता है	हानि होती है
ऋणदाता उपभोक्ता	हानि होती है	लाभावित होता है
स्थिर आय वाले	हानि होती है	लाभावित होता है
अस्थिर आय वाले	लाभावित होता है	हानि होती है
बचत	कमी होती है	वृद्धि होती है
सार्वजनिक ऋण	वृद्धि होती है	कमी होती है
सार्वजनिक व्यय	वृद्धि होती है	कमी होती है
आयत	वृद्धि होती है	कमी होती है
निर्यात	कमी होती है	वृद्धि होती है
औद्योगिक विकास	तीव्र होता है	कमी होती है
रोजगार के अवसरों की उपलब्धता	वृद्धि होता है	कमी होती है
आर्थिक विषमता	बढ़ती	घटती है

बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र का प्रदर्शन	विकास होता है	पतन होता है

Empowering Youth
Empowering Nation
HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!